



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2005/चैत्र 30, 1927

No. 105]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2005/CHAITRA 30, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2005

सं. 3 (आर.ई-2005)/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/हैडबुक/एम 06/पीसी-I.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. “आवेदकों के लिए दिशानिर्देश” शीर्षक अर्थात् ‘आयात निर्यात प्रपत्र’ के पैरा 4.1 के तहत आयातक निर्यातक कोड संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची की क्रम सं० 4 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाता है :

“5. आवेदक की पासपोर्ट साइज़ की फोटो की दो प्रतियाँ जोकि आवेदक के बैंकर द्वारा विधिवत् सत्यापित हों।”

2. परिशिष्ट 26 का पैरा (6) निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

(6) मैं/हम यह भी सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि मैं/..... ने पिछले तीन वर्षों में उसके द्वारा किए गए निर्यातों के लिए निर्यात प्राप्तियों का 95 प्रतिशत अथवा अधिक (आवेदन पत्र भरने की

तारीख से पिछले छः महीनों के दौरान किए गए निर्यात को छोड़कर) और चालू लाइसेंसिंग वर्ष में किए गए निर्यातों के मामले में 90 प्रतिशत वसूल किए हैं जिसके आधार पर मान्यता का दावा किया जा रहा है।

(नया स्तर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लागू)

मैं/हम आगे सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम ने पिछले तीन वर्षों में उसके द्वारा किए गए निर्यातों के लिए निर्यात प्राप्तियों का 95 प्रतिशत अथवा अधिक (आवेदन पत्र भरने की तारीख से पिछले 360 दिनों के दौरान किए गए निर्यात को छोड़कर) और चालू लाइसेंसिंग वर्ष में किए गए निर्यातों के मामले में 90 प्रतिशत वसूल किए हैं जिसके आधार पर मान्यता का दावा किया जा रहा है।

(स्तर प्रमाण पत्र के पुनःनवीकरण के लिए लागू)

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि आवेदक द्वारा किए गए निर्यातों की तारीख से 360 दिनों की अवधि के बाद बकाया निर्यात आमदनी का कुल मूल्य रु० है। (स्तर के पुनःनवीकरण और ई पी सी जी विमुक्ति के लिए मौजूदा स्तर धारकों के मामले में लागू)

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि आवेदक द्वारा किए गए निर्यातों की तारीख से 6 महीने की अवधि के बाद बकाया निर्यात आमदनी का कुल मूल्य रु० है।

(नया स्तर प्रमाण पत्र प्राप्त करने और ईपीसीजी विमुक्ति के लिए लागू)

3. पैरा 2.13 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

“2.13 संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी, जिसने लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र जारी किया था, के द्वारा गुणावगुण के आधार पर लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र का वैधता अवधि की समाप्ति की तारीख से एक बार में छः माह की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है।”

4. पैरा 6.21.1(घ) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

“(घ) ईओयू प्रक्रिया पुस्तक के पैरा-4क.2 के अनुसार उप-ठेके हेतु और अदला-बदली के मद्दे यथा लागू छीजन के लिए पात्र होगा।”

5. उप पैरा 6.27.2 (ग) के बाद, “के.अलावा” शब्दों से शुरू उप-पैरा की पैरा संख्या को उप पैरा 6.27.3 के तौर पर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

“6.27.3 इसके अलावा, विदेश जाने वाले यात्रियों के व्यक्तिगत कैरेज की डाक्यूमेंट अगेन्स्ट एक्सप्टैन्स (डी ए)/ कैश आन डिलवरी (सी ओ डी) के आधार पर अनुमति होगी। ईओयू को निर्यात के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

(क) पोत लदान बिल की प्रतिलिपि;

(ख) निर्यात और आय प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र।”

6. पैरा 9.6 के बाद निम्नलिखित पैरे जोड़े जाएंगे:-

“उपयोग रजिस्टर 9.7 आयातक, लाइसेंस के अधीन आयातित मर्चों और इसके उपयोग के बारे में एक रजिस्टर रखेगा। आयातक, लाइसेंस के बिना आयातित मर्चों और इसके उपयोग के संबंध में एक रजिस्टर भी रखेगा बशर्ते ऐसी मर्चों का आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के तहत किया गया हो।

उन स्कीमों को छोड़कर जिनमें उपयोग रजिस्टर को सुरक्षित रखने हेतु अवधि को विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है, रजिस्टर, परिशिष्ट 23 में दिये गये प्रपत्र के अनुसार रखा जायेगा, अन्य सभी मामलों में रजिस्टर आयात की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक रखा जायेगा।

निर्यात सुविधा 9.8 निर्यातकों की समस्याओं के समन्वित रूप से समाधान के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय निर्यात सुविधा केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे।

ये कार्यालय निर्यातकों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे तथा इनकी व्यापार और निर्यात संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय भी करेंगे।

इसके अतिरिक्त, अन्य मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी भी नामांकित किए गए हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 17 में दी गई है।

विभिन्न विभागों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक विभाग में सुविधा कमेटी का गठन किया जाएगा जिससे विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

स्थायी शिकायत समितियाँ 9.9 शिकायत निवारण तंत्र का ब्यौरा नीति के पैरा 2.49 में दिया गया है।

नीति और प्रक्रिया संबंधी व्यापार और उद्योग की वास्तविक शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत समितियों का गठन किया गया है।

इन शिकायत समितियों के अध्यक्ष (1) मुख्यालय में महानिदेशक, विदेश व्यापार और (2) अलग-अलग लाइसेंसिंग कार्यालयों में संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे।

शिकायत समिति में भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफ आई ई ओ), निर्यात संवर्धन परिषद/वस्तु बोर्ड, विकास प्राधिकरण और सरकारी विभाग/तकनीकी प्राधिकारी, सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

9.9.1 अलग-अलग शिकायत समिति का अध्यक्ष किसी भी सदस्य को शामिल कर सकता है। ऐसी समितियों की बैठकें मासिक आधार पर आयोजित की जाएँगी।

9.9.2 प्रत्येक निर्यातक/आयात को शिकायत समिति में अभ्यावेदन देने तथा यदि वह चाहे तो व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अधिकार होगा। इस प्रयोजन के लिए वह व्यक्तिगत सुनवाई के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है।

9.9.3 शिकायत समिति को अभ्यावेदन परिशिष्ट-26 में दिए गए प्रपत्र में भेजा जाएगा ।”

7. पैरा 9.12 संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

“निर्यात के संबंध में शिपमेंट/प्रेषण की तारीख 9.12 निर्यात के उद्देश्य के लिए शिपमेंट/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जायेगा:-

परिवहन का तरीका

शिपमेंट/प्रेषण की तारीख

1. समुद्र मार्ग द्वारा

बल्क कार्गो के लिए, लदान-पत्र की तारीख या नेट रसीद की तारीख, जो भी बाद की हो।

क. कंटेनर-युक्त कार्गो के लिए, " जहाज पर लदान बिल " की तारीख जहाँ एल/सी में ऐसे लदान-पत्र की व्यवस्था है। अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो (आई सी डी) से कंटेनरों द्वारा निर्यात के लिए, सीमाशुल्क क्लीअरेंस के पश्चात आई सी डी में लदान के समय शिपिंग एजेंटों द्वारा जारी किए गए लदान-बिल की तारीख।

ख. लैश बार्जेज के लिए, लदान-बिल की तारीख जिसमें जहाज पर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लदान का प्रमाण हो।

2. वायु मार्ग द्वारा

उपयुक्त सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा शिपिंग बिल पर उल्लिखित तारीख, जिसमें लदान या वस्तु कार्गो काम्प्लैक्स, जो अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है, को माल सौंपने का या उड़ान संख्या और तारीख का प्रमाण हो।

3. डाक पार्सल द्वारा

डाक रसीदी पर अंकित तारीख।

4. रेल द्वारा

रेलवे रसीद की तारीख।

127/ 8/ 2008-2

5. पंजीकृत कुरिअर सेवा कुरिअर रसीद/माल-सूची पर अंकित द्वारा तारीख।

6. सड़क मार्ग द्वारा जैसा कि भूमि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया है, भारतीय सीमा से माल बाहर जाने की तारीख।

तथापि, जहाँ कहीं नीति सम्बंधी उपबंधों को निर्यातकों के अहित में संशोधित किया गया है, तो इस सार्वजनिक सूचना की तारीख तक जाँच के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी को पहले से ही सौंपे गए कन्साइन्मेंटों और बाद में निर्यातों पर लागू नहीं होंगे।

इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहाँ निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति से पहले माल सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंप दिया, जाता किन्तु वास्तविक निर्यात, निर्यात दायित्व की अवधि की समाप्ति के बाद किए जाते हैं, तो ऐसे निर्यातों पर निर्यात दायित्व अवधि के भीतर विचार किया जाएगा और निर्यात दायित्व की पूर्ति की जाएगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th April, 2005

No. 3(RE-2005)/2004—2009

F. No. 01/94/180/Handbook/AM 06/PC-L—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures (Vol. I):—

1. After Sl.No.4 of the list of documents to be annexed to the application for obtaining Importer Exporter Code Number under the heading “Guidelines for applicants”, i.e. para 4.I of ‘Aayaat Niryaat Form’ the following is added:

“5. Two copies of passport size photographs of the applicant duly attested by the Banker of the applicant”.

2. Para (vi) of Appendix 26 is amended to read as under:-

“(vi) I/We further certify that M/s..... has realised 95% or more of the export proceeds in respect of exports

made by him in the preceding three licensing years [excluding the export made during last six months from the date of filing of application] and 90% in the case of exports made in the current licensing year on the basis of which recognition is being claimed. (applicable for obtaining status certificate afresh)

I/We further certify that M/s..... has realised 95% or more of the export proceeds in respect of exports made by him in the preceding three licensing years [excluding the export made during last 360 days from the date of filing of application] and 90% in the case of exports made in the current licensing year on the basis of which recognition is being claimed. (applicable for renewal of status)

I/We hereby certify that the total value of outstanding export proceeds beyond a period of 360 days from the date of exports made by the applicant is Rs._____ (applicable in case of existing status holders for renewal of status and for EPCG redemption).

I/We hereby certify that the total value of outstanding export proceeds beyond a period of 6 months from the date of exports made by the applicant is Rs._____ (applicable for obtaining status certificate afresh and for EPCG redemption)."

3. Para 2.13 is amended to read as under:

"2.13 The licence/certificate/permission may be revalidated on merits by the licensing authority concerned, which has issued the licence/certificate/permission, for a period of six months reckoned from the date of expiry of the validity period."

4. Para 6.21.1(d) is amended to read as under:-

"(d) EOUs shall be eligible for wastage as applicable as per para 4A.2 of Handbook for sub-contracting and against exchange."

5. After sub para 6.27.2(c), para no. of the sub para beginning with the words "In addition", is renumbered as sub para 6.27.3 which reads as under:-

"6.27.3 In addition to this, Personal Carriage by foreign bound passenger on Document Against Acceptance (DA)/Cash On Delivery (COD) basis is also allowed. The EOUs will have to furnish the following documents as proof of exports:-

(a) Copy of Shipping Bill;

(b) Bank Certificate of Export and Realisation."

6. After Para 9.6 following paras are added:-

"Consumption Register 9.7 The importer shall maintain a register of items imported under a licence and its consumption. The importer shall also maintain such a register of items imported without a licence and its consumption provided such items are imported subject to actual user condition.

The register shall be maintained in the form given in Appendix-23 except in respect of the scheme wherein period for retention of the consumption register is specifically mentioned, in all other cases, the register shall be maintained upto 3 years period from the date of import.

Export Facilitation 9.8 In order to resolve exporters' problems in a co-ordinated manner, the field offices of the Directorate General of Foreign Trade shall act as Export Facilitation Centres.

These offices shall function as nodal agencies to attend to the problems and grievances of the exporters, and also co-ordinate with different Departments to resolve their trade and export related problems.

In addition, Nodal Officers have also been nominated in other Ministries/ Departments and a list of such officers nominated to assist exporters is given in Appendix-17.

For resolving problems relating to different departments, facilitation committees shall be constituted in each department which shall be serviced by Directorate General of Foreign Trade.

Standing Grievance Committee 9.9 The detail of the Grievance Redressal Mechanism is given in para 2.49 of the Policy.

In order to facilitate speedy redressal of genuine grievances of trade and industry pertaining to the Policy and Procedure, Grievance Committees have been constituted.

These Grievance Committees are chaired by (i) the Director General of Foreign Trade at the Headquarters and (ii) head(s) of the concerned Regional Licensing Authority (s) in the respective licensing offices.

Grievance Committee will include representatives of the Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Export Promotion Councils/ Commodity Boards,

- Development Authorities, and Government Departments/ technical authorities as their members.
- 9.9.1 The Chairman of the respective Grievance Committee(s) may also co-opt any other member. The meetings of such Committees shall be held on a monthly basis.
- 9.9.2 Every exporter/importer shall have a right to seek and have an opportunity to make a representation to and be personally heard, if he so desires, by the Grievance Committee. For this purpose, he may send his request in writing seeking such personal hearing.
- 9.9.3 A representation to the Grievance Committee may be made in the form given in Appendix-26."

7. Para 9.12 is amended to read as under:

"Date of Shipment/Dispatch respect of Exports" of 9.12 Date of shipment/despatch for the purposes of exports will be reckoned as under:-

Mode of Date Of Shipment/ Dispatch Transportation

(i) By Sea

For bulk cargo, the date of Bill of Lading or the date of receipt, whichever is later.

a) For containerised cargo, the date of "Onboard Bill of Lading", or "Received for Shipment Bill of Lading", where the L/C provides for such Bill of Lading. For exports by containers from Inland Container Depot (ICD), the date of Bill of Lading issued by shipping agents at the time of loading of export goods in the ICD after customs clearance.

b) For Lash barges, the date of Bill of Lading evidencing loading of the export goods on board

(ii) By Air

The date mentioned by the appropriate Officer of Customs on the Shipping Bill, evidencing loading or handing over of goods to the air cargo complex, which are not

1271 9272005-3

	international airports, or by way of rotation of flight number and date.
(iii) By Post Parcel	The date stamped on the postal receipt.
(iv) By Rail	The date of RR (Railway Receipt).
(v) By Registered Courier Service	The date affixed on Courier Receipt/ Waybill
(vi) By Road	The date on which the goods crossed the Indian border as certified by the Land Customs Authorities.

However, wherever the Policy provisions have been modified to the disadvantage of the exporters, the same shall not be applicable to the consignments already handed over to the Customs for examination and subsequent exports upto the date of the Public Notice.

Similarly, in such cases where the goods are handed over to the customs authorities before the expiry of the export obligation period but actual Exports take place after expiry of the export obligation period, such exports shall be considered within the export obligation period and taken towards fulfilment of export obligation."

This issues in Public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade and ex-officio Addl. Secy.